

क्या एक और तख्तापलट की ओर बढ़ रहा है पाकिस्तान

अंजन कुमार

नई दिल्ली : पाकिस्तान में एक बार फिर से सैन्य तखापलट की आहट नजर आ रही है। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी

“असीम मुनीर ने जब से पाकिस्तानी फौज की कमान संभाली है, उनकी मुस्लिम कटूता और हिंदू विशेष वाली मानसिकता देखते हुए ऐसा माना जाता रहा है कि वह मुल्क के कुछ गिने-चुने लेकिन, सबसे ताकतवर नेताओं में खुद का नाम शुमार करना चाहते हैं। इनमें भारत के बंटवारे और लाखों लोगों के नरसंहर के लिए जिसमें अली जिन्ना, जनश्वर जिया-उल-हक और जनश्वर परवेज मुशर्रफ जैसे कुख्यात पाकिस्तानी शारिस्यतें शामिल हैं। पाकिस्तान में फील्ड मार्शल बनने के बाद जनश्वर मुनीर को एक नई ताकत मिली है। इससे सेना में उनका दबदबा और बढ़ सकता है। फौज में उनके जो विशेषी हैं, उन्हें कुछ समय के लिए जोर का झटका लगा है और फिल्हाल के लिए वह पीछे हटने को मजूब रहते हैं। मुनीर पहले से ही खुद को इष्टवादी दिखाने के लिए धार्मिक उन्माद फैलाने वाली बातें कर रहे हैं। जिस समय पाकिस्तान की आर्थिक हालत बेहद रख रही है, कर्ज न मिले तो आटा नुटाने में आफत है, फिर भी वे कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की ढांच लगा रहे हैं। उन्होंने कश्मीर मुद्दे के अंतर्राष्ट्रीय करण के लिए तुर्की, अमेरिका और चीन से भी समर्थन मांगा है। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से जिस तरह से मंगलवार को अचानक मुनीर के प्रमोशन की बड़ी खबर आई, उसको लेकर कुछ विशेषकों को तो यहां तक लग रहा है कि फील्ड मार्शल बनाए जाने का मतलब है कि उन्हें संभावित कोर्ट मार्शल की स्थिति से सुरक्षित कर दिया गया।



The image consists of two parts. On the right side, there is a close-up portrait of General Mian Naeem, wearing a military uniform with a gold-colored peaked cap featuring a golden emblem. He has a mustache and is looking slightly to the right. On the left side, there is a block of text in Hindi. The text discusses General Mian Naeem's views on India's role in the Kargil War, mentioning his criticism of Prime Minister Atal Bihari Vajpayee and his support for a more assertive military stance.

क्या एक उम्मीद
रहा है पाकिस्तान
पाकिस्तान के लोग
भी यह बात बहुत
में हुआ करगी।
पाकिस्तानी लोग
उनकी सरकार
बना। कर्गिल
परवेज मुशर्रफ
थी, जिस तरह
का ताना-बाना
असीम मुनीराह
और पाकिस्तान
आरोपों से कर्तव्य
के दौरान परवर्त्य
था। लेकिन,
द लाइन ऑफ
मान लिया फैला
पाकिस्तानी पास
पहले पाकिस्तान
छिपे कब्जे :
झाड़ रहा था।
इस युद्ध में पास
चटा दिया और
जनता और प्रधान
लगे तो कुछ
अक्टूबर में
तख्तापलट व

र तत्खापलट की ओर बढ़
स्तान : कुछ समय पहले
पूर्व पीएम मियां नवाज शरीफ
बूल कर चुके हैं कि 1999
ल युद्ध ही तत्कालीन जनरल
जनरल परवेज मुशर्रफ द्वारा
र के तत्खापलट का कारण
त युद्ध की साजिश जनरल
ने लगभग उसी तरह से रची
ह से पहलगाम आतंकी हमले
ना बुनने का संदेह जनरल
पर जताया जा रहा है। मुनीर
तानी सरकार लगातार इन
न्नी काट रहे हैं। करगिल युद्ध
परवेज मुशर्रफ ने भी यही किया
2006 में अपनी किताब 'इन
फायरफायर में उसने खुद
कि करगिल युद्ध के पीछे
कौज का हाथ था। जबकि,
न भारतीय चौकियों पर चोरी-
की अपनी करतूतों से पल्ला
लेकिन, जब भारतीय सेना ने
किस्तान को बुरी तरह से धूल
र जनरल मुशर्रफ पाकिस्तानी
कौज के बीच कमजोर पड़ने
ही महीने बाद 1999 के
नवाज शरीफ सरकार का
कर दिया और पाकिस्तान में

। असीम मुनीर की वह अपने गुरु के नने की कोशिश कर उज के भाई शहबाज बकरा बन सकते हैं। फ असीम मुनीर के ले साल सिर्टर्बर में वर्जनिक तौर पर मान युद्ध में पाकिस्तानी फ ने जब यह कबूल छ भी नहीं रह गए थे। ल रहते हुए यह बात भी पाकिस्तानी रक्षा आयोजित कार्यक्रम न युद्ध के दौरान भी बन गए थे, जो रान बने। पाकिस्तान बचाने के लिए खुद का ने उसपर कर्गिल घटने का दबाव बनाया पाकिस्तानी फौज ने उनको निजी 'स्वतंत्रता गोशिश की थी। इस ने कुछ कहा था, वह था, जो पाकिस्तान के देखने को मिला है। किस्तान एक बहादुर आजादी का महत्व समझते हैं। वे इसे किसी भी कीमत पर बचाने के लिए तैयार रहते हैं। 1948, 1965, 1971 के भारत-पाक युद्ध हुए। करिगिल और सियाचिन में भी लड़ाई हुई। हजारों शहीदों ने देश की सुरक्षा और सम्मान के लिए शहदर्ते ही।

पाकिस्तानी सेना ने मुल्क में कब-कब किया तखापलट: क्या पाकिस्तान में सब ठीक है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है, क्योंकि देश में पहले भी तीन बार सेना ने तखापलट किया है। जनरल अबूब खान ने 1958 में, जनरल जिया-उल-हक ने 1977 में और जनरल परवेज मुशर्रफ ने 1999 में हुकूमत पर कब्जा किया था। अब क्या जनरल मुनीर भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं? जनरल अबूब खान ने राष्ट्रपति इस्कंदर अली मिजाहियरों के दम पर सत्ता छीन ली। इसके बाद 1977 में जनरल जिया-उल-हक ने वही किया। फिर 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की सरकार को तब सत्ता से बेदखल कर दिया, जब वे विदेश दौरे पर श्रीलंका गए हुए थे। इन तखापलटों की वजह से पाकिस्तान वर्षों तक मिलिट्री रूल के अधीन रहा है। संयोग से अभी ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान हारा है और पाकिस्तान की सरकार की कमान नवाज के भाई शहबाज शरीफ के हाथों में है।

ਕੇਂਦ੍ਰ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਸ਼ਾਲਿਨ ਸਰਕਾਰ

वन पाड्य

तामिलनाडु सरकार न कद्र सरकार क खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। यह याचिका समग्र शिक्षा योजना के तहत 2000 करोड़ से ज्यादा फंड रोके जाने को लेकर है। राज्य सरकार का आरोप है कि उसने नई शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 को लागू नहीं किया, इसलिए केंद्र ने फंड जारी नहीं किया।



आधानयम् 2010' (रिट टू
एज्युकेशन एक्ट) के तहत अपनी
जिम्मेदारी निभाते हुए हर शैक्षणिक
वर्ष की शुरुआत से पहले 60%
खर्च की राशि समय पर देनी चाहिए।
हिंदी थोपने का लगाया आरोप :
राज्य सरकार ने यह भी आरोप लगाया
है कि केंद्र सरकार नई शिक्षा नीति के
जरिए हिंदी थोपने की कोशिश कर रही
है। तमिलनाडु सरकार लंबे समय से
तीन-भाषा फॉर्मूला का विरोध करती
रही है और दो टूक कहती रही है कि
राज्य में हिंदी नहीं थोपी जा सकती।

क्या है सुप्रीम काट का पुराना फैसला? : कुछ समय पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने एक जननित याचिकाखारिंज की थी, जिसमें तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल में तीन-भाषा फॉर्मूला लागू करने की मांग की गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान जरिस्म जेबी पारदीवाला की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा था कि, 'कोई अदालत सीधे किसी राज्य को नई शिक्षा नीति जैसे किसी नीति को लागू करने का आदेश नहीं दे सकती'। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर

किसा राज्य का करवाई स मालिक
अधिकारों का हनन हो रहा हो, तभी
हस्तक्षेप किया जा सकता है। कोर्ट ने
याचिकाकर्ता की मंशा पर भी सवाल
उठाते हुए कहा कि वह दिल्ली में रहता
है और उसका सीधे कोई लेना-देना
इस मुद्दे से नहीं है। नई शिक्षा नीति
2020 केंद्र सरकार द्वारा लाइ गई थी
जिसमें कई बड़े बदलावों का प्रस्ताव
था, जैसे कि $5+3+3+4$ शिक्षा
ढांचा, मातृभाषा में पढ़ाई को बढ़ावा,
तीन-भाषा फॉर्मूला, उच्च शिक्षा में
व्यापक सुधार।

क्या तुर्की में कांग्रेस दफ्तर है, अमित मालवीय व अर्नब गोस्वामी पर केस, गोस्वामी ने माफी मांगी

कांग्रेस ने बीजेपी का और रिपब्लिक टेल संपादक अर्नब गोविंद पुलिस में शिकायत पर कांग्रेस के तुकी की दुर्भावना पूर्ण गया का आरोप लगाया पोस्टमें "विपक्ष के के संवैधानिक पद भी उल्लेख किया कांग्रेस ने जैसे ही पूर्णी, अर्नब गोविंद विवाद से पीछा छुट्टा पहले भी विवादों में मांग चुका है। कांग्रेस कहा कि यह पार्टी अशांति भड़काने, कमज़ोर करने और हमला करने का दुर्भाव था। हम चुप नहीं पोस्ट में कहा- यह है: हमारी पार्टी या खिलाफ़ फर्जी रुक़िया किसी भी कोशिश और राजनीतिक ज़रूरत में कि मालबीय और फर्जी दावा फैला



इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कार्यालय है। यह कृत्य स्पष्ट और निर्विवाद रूप से आपराधिक इंद्रे के साथ किया गया था ताकि भारतीय जनता को धोखा दिया जाए। एक प्रमुख राजनीतिक संस्थान की मानवानि की जाए, राष्ट्रवादी भावनाओं में हेरफेर किया जाए, जन अशांति भड़काई जाए, और राष्ट्रीय सुरक्षा और लोकतांत्रिक अखंडता को कमज़ोर किया जाए। उन पर जानबूझकर और आपराधिक रूप से प्रेरित अभियान का मास्टरमाइंड होने का आरोप लगाया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से गलत जानकारी फैलाई गई। ऑपरेशन सिंटूर के दौरान पाकिस्तान को तुर्की के समर्थन के बाद से देश में जनता का मूढ़ तुर्की के खिलाफ वैसे भी बहुत खिलाफ चल रहा है। इन दोनों

माहौल को भुनाने और उसका रुख
कांग्रेस की आर मोड़ने की खतरनाक
कोशिश की। एक पत्रकार पर सत्य
बताने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती
है। लेकिन अनंव गोस्वामी तो सफेद
झूट फैला रहे थे। तुर्की में दूर-दूर तक
कांग्रेस दफ्तर नहीं और वहाँ भारत की
प्रमुख विपक्षी पार्टी का दफ्तर बताकर
जनता को गुमराह किया जा रहा है।
तुर्की के खिलाफ भारत में ऐसा
माहौल है कि वहाँ धूमने जाने वालों
ने अपनी बुकिंग रद्द की है। देश के
तमाम विश्वविद्यालयों ने तुर्की के
शिक्षण संस्थानों के साथ कार्यक्रम रद्द
कर दिए हैं। भारत में काम कर रही
तुर्की की फर्मों को बाहर का गस्ता
दिखाया गया है। सेलेबी के 2700
कर्मचारियों की नैकरी पर खतरा
मंडरा रहा है। कांग्रेस ने कहा कि यह
सुनियोजित अभियान के बल एक

नैतिक चूक नहीं है, बल्कि एक जानबूझकर किया गया आपाराधिक घट्टांत्र है, जिसे जनता को नुकसान पहुंचाने, राष्ट्र को अस्थिर करने और पक्षपातपूर्ण एंडेंडों को बढ़ावा देने के लिए पूर्व नियोजित रूप से अंजाम दिया गया। आरोपियों ने अपनी प्रभावशाली स्थिति का दुरुपयोग किया है। मालवीय ने एक प्रमुख राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में और गोस्वामी ने एक प्रमुख मीडिया हस्ती के रूप में-सत्य, जन सुक्ष्मा और राष्ट्रीय हित पर गंभीर हमला किया है। अमित मालवीय और अर्नब गोस्वामी का यह नया कारनामा नहीं है। दोनों पर कांग्रेस पार्टी ने पहले भी झूठ फैलाने का आरोप लगाया है। अर्नब गोस्वामी के चैनल पर तो बॉलीवुड को लेकर भी तमाम झूठ फैलाए गए।

हिमंत-आईएसआई के निमंत्रण पर पाक गए थे गोगोई कांग्रेस नेता - '500 रुपये के बीजेपी ट्रोल जैसे'

“ गौरव गोगोई ने सरमा के आयेपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे 'बी ग्रेड फ़िल्म की स्क्रिप्ट से भी बढ़तर' बताया। उन्होंने कहा कि सरमा उनके एजनीटिक करियर की शुरुआत से ही उन पर झूठे और नियधार आयेप लगा रहे हैं। गोगोई ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, 'आप एक मुख्यमंत्री हैं। आपके और 500 रुपये के बीजेपी ट्रोल में कुछ तो अंतर होना चाहिए। जो बातें सोशल मीडिया पर सस्ते ट्रोल फैलाते हैं, वही बातें आप कह रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, 'सरमा के 99% ढावे झूठे, हस्यास्पद और बकवास हैं। गोगोई ने यह भी सवाल उठाया कि यदि सरमा के पास कोई ठोस सबूत हैं तो वे उन्हें सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे।



उन्हान कहा, 'सरमा इ
जाएंगे। हिमंत बिस्वा सरमा ने पहले भी
गोगोई पर आरोप लगाया था कि उन्होंने
संसद में ऐसे सवाल उठाए जो 'पाकिस्तानी
सेना की मदद' करने वाले थे।
गोगोई का तीखा पलटवारः गैरव गोगोई

A close-up portrait of a man wearing glasses and a white shirt.

उठाकर राष्ट्रीय हितों के खलिअफ़ काम किया है। गोगोई ने इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि सरमा का मक्सद केवल उनकी छवि को धूमिल करना और राजनीतिक लाभ लेना है। इस ताजा विवाद ने असम की राजनीति में हलचल मचा दी है। सोशल मीडिया पर इस मुद्दे पर तीखी बहस छिड़ गई है। कुछ यूजर्स ने सरमा के दावों का समर्थन करते हुए गोगोई पर देशद्राही होने का आरोप लगाया, जबकि अन्य ने गोगोई का पक्ष लेते हुए सरमा पर घटिया राजनीति करने का आरोप लगाया। कांग्रेस पार्टी ने भी इस मामले में गोगोई का समर्थन किया है और सरमा के बयानों की निंदा की है। पार्टी के प्रवक्ताओं ने इसे बीजेपी की विभाजनकारी रणनीति बताया है जिसका उद्देश्य असम में कांग्रेस के प्रभाव को कम करना है। इस विवाद ने भारत-पाकिस्तान के बीच संवेदनशील मुद्दों को एक बार फिर सुरिखियों में ला दिया है। मग्ना टाग गिरित पारम्पर्यादी की जग्ज

संक्षिप्त समाचार

डॉ. अम्बेडकर पुस्तकालय में सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए विशेष कक्ष का आयोजन किया गया

देवघर से दिव्य दिनकर संवाददाता प्रेम रंजन झा

[देवघर]: सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए, Udaan IAS Academy, Ranchi द्वारा एक विशेष कक्ष का आयोजन डॉ. अम्बेडकर पुस्तकालय, देवघर में किया गया। इस रैली में पार्टी के कई शीर्ष नेताओं ने भाग लिया और केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार पर संविधान में छेड़छाड़ करने से तथा उसे बदलने का प्रयास कांगड़ी आरोप लगाया। प्रदेश अध्यक्ष शेखाव महाराज कमलेश ने संविधान में कहा कि कांगड़े ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, लोकतांत्रिक व्यवस्था के कायम करने के लिए, संविधान दिया, आज उस संविधान के पनों के साथ केंद्र की मोदी सरकार द्वारा छेड़छाड़ करना चाहिए और केंद्र में संविधान के लिए संवैधानिक संस्थाओं को कमज़ोर करने हुए उसका दुरुपयोग भी कर रहा है। इसलिए आज देवघर सिविलों को यह संदेश घर-घर तक पहुंचने का काम है कि हमारे लोकतंत्र को जीवित रखने एवं अपने अधिकार बरकरार रखने के लिए संविधान की रक्षा करने की जरूरत है। आज राहुल गांधी सड़क से सदन तक संविधान की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। संविधान के अधिकार के तहत आज संस्थान परगना में एस.पी.टी. एकट का अधिकार मिला है। इस अधिकार के साथ सांचालिक आधिकारिक निवासक और आधिकारिक निवासक एवं न्याय का अधिकार देता है, हर व्यक्ति को सांचालिक का अधिकार मिला है। इसे में संविधान की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। इस देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में पूज्य वापू पंडित नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे महायुगों को संरेख्य का परिणाम है। देश की आजादी में रस एवं भारतीय जनता पार्टी के किसी भी सदृश्य ने एक बूंद खून नहीं बही नहीं इस आदेलन में कभी हिस्सा लिया बदले अग्रिमों को चाटकरिता करते रहे उनके मुख विधि करते रहे। 58 वर्षों तक अपने कायांलय में कभी तिरंगा नहीं लहराया। जिह्वोंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को जिह्वोंने दूसरा संविधान एवं रस पर जिला स्तर पर, विधानसभा स्तर पर रैलियां निकाली जाएँगी तपश्चात हर घर एवं हर व्यक्ति तक यह संदेश घर-घर तक पहुंचाया जाएगा कि आज हमारे संविधानको बदलने का प्रयास किया जा रहा है, उसके साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। इस कैप का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ, जिसमें मुख्य अधिकारी के रूप में चतुर्वार्षिक व्यवस्था की रक्षा की लड़ाई में देश के हर एक घर एवं परिवार के लोगों को संदेश पहुंचाते हुए इस मुहिम में शामिल कराया गया। जब संविधान बचेगा तभी देश बचेगा। उसके लिए सभी पार्टी के नेता एवं कायांलयों में जोश भरे हैं। गोद्धु में अपनी जीवन की आजादी की नींदों दी उठें भी नाश्रम गोद्दे के द्वारा हत्या कराया गया। आजादी के बाद संविधान निर्माण में संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद एवं मर्यादा संपत्ति अध्यक्ष डॉ. अम्बेडकर बने। संविधान निर्माण में जारखंड का वर्कर की स्थानों में उनका योगदान अद्यत है जिसे परीक्षाओं और सिद्धांत आज भी हम सभी के लिए प्रेया है। औक पर सुधों से रोने, हीरा वादव, राजकुमार मिश्र उर्फ संटी मिश्र समेत अन्य जेएमएस सदस्य मौजूद थे।

स्व दुर्गा सोरेन की पृष्ठातिथि पर विधायक ने किया माल्यार्पण, दी श्रद्धांजलि



मंडरो: जारखंड को विहार से अलग राज्य बनाने के संघर्ष में दिशेम गुरु शिवू सोरेन के साथ कधे से कंधा मिलाकर चलें वाले स्व दुर्गा सोरेन की 15वीं पृष्ठातिथि मंडों में बोरियो विधानसभा विधायक धनंजय सोरेन, जेएमएस जिलाध्यक्ष अरुण कुमार सिंह, केंद्रीय समिति सदस्य संजय मिश्र उर्फ बबलु मिश्र समेत अन्य जेएमएस सदस्यों ने स्व दुर्गा सोरेन की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उठें भावूपूर्ण श्रद्धांजलि दी। वही बोरियो विधानसभा विधायक धनंजय सोरेन ने कहा की दादा दुर्गा सोरेन का जीवन हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। जारखंड राज्य अदेलन के महान योद्धा समाजसेवी और क्रांतिकारी स्वर्गीय दुर्गा सोरेन का उनकी पुण्यतिथि पर शत-शत नम उड़ाने जीवन संवर्धन की पीढ़ी के लिए बढ़ावा देता है। उनकी विधायकांग और सिद्धांत आज भी हम सभी के लिए प्रेया है। औक पर सुधों से रोने, हीरा वादव, राजकुमार मिश्र उर्फ संटी मिश्र समेत अन्य जेएमएस सदस्य मौजूद थे।

साथी अभियान : एक भी बच्चा न छूटे, कानूनी पहचान की ओर कदम कार्यक्रम का आयोजन

साहिबगंजः जारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, राज्यी के निर्देश पर साहेबगंज जिले में हास्याथीढ़ अभियान की तैयारियों जोरों पर है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, श्री अखिल कुमार के मार्गदर्शन और सचिव विश्वनाथ भगत के नेतृत्व में वह पहल निराश्रित एवं असहाय बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए शुरू की गई है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, नई दिल्ली द्वारा प्रारंभ इस अभियान के तहत 26 मई से 26 जून 2025 तक एक माह का सधन पहचान अधिकारीय जलाया जाएगा। इसका उद्देश्य ऐसे बच्चों को पहचान कर उनका आधार पंजीकरण कराना और उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, सुकृति तथा अन्य संरक्षण को जोड़ना है। समिति के सम्बन्धित क्रियान्वयन हेतु 'साथी जिला समिति' का गठन किया गया है, जिसकी अधिकारीय जिला संविधान भगत कर रहे हैं। समिति में महिला एवं बाल कल्याण, सिक्षा, स्वास्थ्य, आधार पंजीकरण पदाधिकारी, बालग्राहों के प्रतिनिधि, अधिवक्तागण और पीपलवी से जोड़ने के लिए बालग्राहों के लिए विधिक सेवा प्राधिकार, अन्वेषण और समाजसेवा एवं आधारीय अभियान के तहत 26 मई से 26 जून 2025 तक एक माह का सधन पहचान अधिकारीय जलाया जाएगा। इसका उद्देश्य ऐसे बच्चों को पहचान कर उनका आधार पंजीकरण कराना और उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, सुकृति तथा अन्य संरक्षण को जोड़ना है। समिति के सदस्यों को अवगत कराया जाएगा। यह भी निर्णय लिया गया कि अभियान का प्रचार-प्रसार प्रखंड और तालुका स्तर तक किया जाएगा। जिसके कारण बच्चों को न सिर्फ कानूनी पहचान दिलाने का बालग्राहों के लिए विधिक सेवा प्राधिकार, नई दिल्ली द्वारा प्रारंभ इस अभियान के तहत 26 मई से 26 जून 2025 तक एक माह का सधन पहचान अधिकारीय जलाया जाएगा। इसका उद्देश्य ऐसे बच्चों को पहचान कर उनका आधार पंजीकरण कराना और उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, सुकृति तथा अन्य संरक्षण को जोड़ना है। समिति के सदस्यों को अवगत कराया जाएगा। यह भी निर्णय लिया गया कि अभियान का प्रचार-प्रसार प्रखंड और तालुका स्तर तक किया जाएगा। जिसके कारण बच्चों को न सिर्फ कानूनी पहचान दिलाने का बालग्राहों के लिए विधिक सेवा प्राधिकार, नई दिल्ली द्वारा प्रारंभ इस अभियान के तहत 26 मई से 26 जून 2025 तक एक माह का सधन पहचान अधिकारीय जलाया जाएगा। इसका उद्देश्य ऐसे बच्चों को पहचान कर उनका आधार पंजीकरण कराना और उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, सुकृति तथा अन्य संरक्षण को जोड़ना है। समिति के सदस्यों को अवगत कराया जाएगा। यह भी निर्णय लिया गया कि अभियान का प्रचार-प्रसार प्रखंड और तालुका स्तर तक किया जाएगा। जिसके कारण बच्चों को न सिर्फ कानूनी पहचान दिलाने का बालग्राहों के लिए विधिक सेवा प्राधिकार, नई दिल्ली द्वारा प्रारंभ इस अभियान के तहत 26 मई से 26 जून 2025 तक एक माह का सधन पहचान अधिकारीय जलाया जाएगा। इसका उद्देश्य ऐसे बच्चों को पहचान कर उनका आधार पंजीकरण कराना और उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, सुकृति तथा अन्य संरक्षण को जोड़ना है। समिति के सदस्यों को अवगत कराया जाएगा। यह भी निर्णय लिया गया कि अभियान का प्रचार-प्रसार प्रखंड और तालुका स्तर तक किया जाएगा। जिसके कारण बच्चों को न सिर्फ कानूनी पहचान दिलाने का बालग्राहों के लिए विधिक सेवा प्राधिकार, नई दिल्ली द्वारा प्रारंभ इस अभियान के तहत 26 मई से 26 जून 2025 तक एक माह का सधन पहचान अधिकारीय जलाया जाएगा। इसका उद्देश्य ऐसे बच्चों को पहचान कर उनका आधार पंजीकरण कराना और उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, सुकृति तथा अन्य संरक्षण को जोड़ना है। समिति के सदस्यों को अवगत कराया जाएगा। यह भी निर्णय लिया गया कि अभियान का प्रचार-प्रसार प्रखंड और तालुका स्तर तक किया जाएगा। जिसके कारण बच्चों को न सिर्फ कानूनी पहचान दिलाने का बालग्राहों के लिए विधिक सेवा प्राधिकार, नई दिल्ली द्वारा प्रारंभ इस अभियान के तहत 26 मई से 26 जून 2025 तक एक माह का सधन पहचान अधिकारीय जलाया जाएगा। इसका उद्देश्य ऐसे बच्चों को पहचान कर उनका आधार पंजीकरण कराना और उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, सुकृति तथा अन्य संरक्षण को जोड़ना है। समिति के सदस्यों को अवगत कराया जाएगा। यह भी निर्णय लिया गया कि अभियान का प्रचार-प्रसार प्रखंड और तालुका स्तर तक किया जाएगा। जिसके कारण बच्चों को न सिर्फ कानूनी पहचान दिलाने का बालग्राहों के लिए विधिक सेवा प्राधिकार, नई दिल्ली द्वारा प्रारंभ इस अभियान के तहत 26 मई से 26 जून 2025 तक एक माह का सधन पहचान अधिकारीय जलाया जाएगा। इसका उद्देश्य ऐसे बच्चों को पहचान कर उनका आधार पंजीकरण कराना और उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, सुकृति तथा अन्य संरक्षण को जोड़ना है। समिति के सदस्यों को अवगत कराया जाएगा। यह भी निर्णय लिया गया कि अभियान का प्रचार-प्रसार प्रखंड और तालुका स्तर तक किया जाएगा। जिसके कारण बच्चों को न सिर्फ कानूनी पहचान दिलाने का बालग्राहों के लिए विधिक सेवा प्राधिकार, नई दिल्ली द्वारा प्रारंभ इस अभियान के तहत 26 मई से 26 जून 2025 तक एक माह का सधन पहचान अधिकारीय जलाया जाएगा। इसका उद्देश्य ऐसे बच्चों को पहचान कर उनका आधार पंजीकरण कराना और उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, सुकृति तथा अन्य संरक्षण को जोड़ना है।

विकसित भारत के अमृत स्टेशन



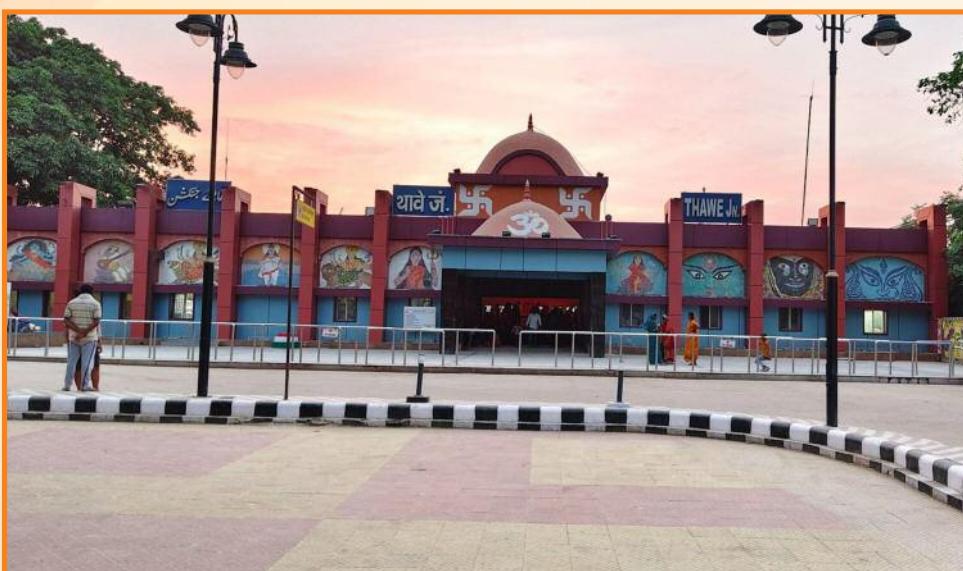
देश भर में

पुनर्विकसित **103** अमृत स्टेशनों का

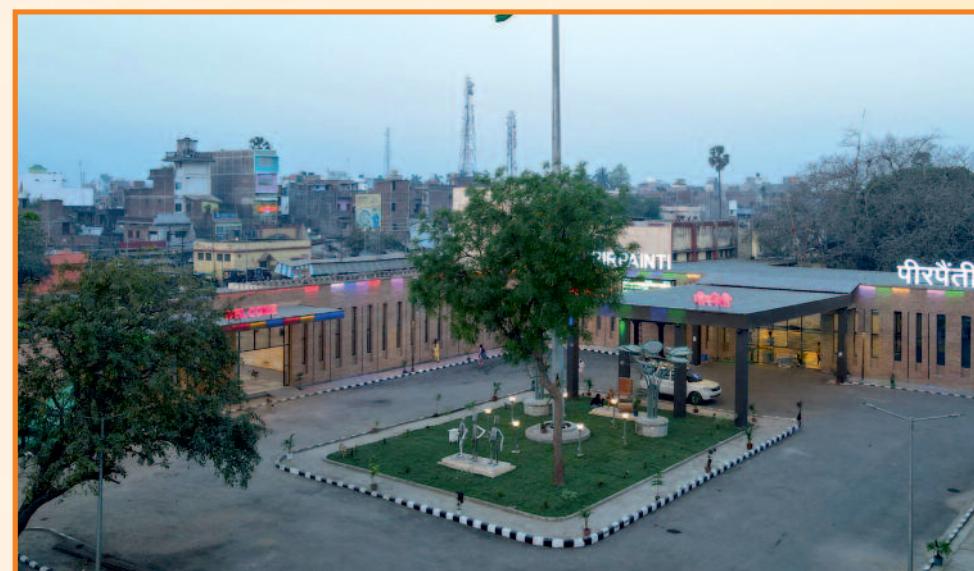
उद्घाटन

जिसमें शामिल हैं

बिहार के **2** अमृत स्टेशन



थावे जं.



पीरपेंती

लाभ

- सिटी सेंटर के रूप में विकास - विश्राम कक्ष, विशाल परिसंचारी क्षेत्र आदि जैसी सुविधाएं
- विरासत भी विकास भी - स्थानीय वास्तुकला से प्रेरित स्टेशन भवन
- अलग-अलग प्रवेश और निकास द्वारा, बेहतर पार्किंग, लाउंज, प्रतीक्षालय, दिव्यांगजन अनुकूल सुविधाएं
- मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के एकीकरण से ये स्टेशन बनेंगे क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों के केन्द्र
- स्टेशनों के डिज़ाइन में ऊर्जा दक्षता और हरित उपायों को प्राथमिकता, जिससे न्यूनतम पर्यावरणीय प्रभाव

प्रधानमंत्री
नरेन्द्र मोदी

के कर कमलों द्वारा

(वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से)

22 मई, 2025 | प्रातः 10:30 बजे

गटिमानी उपस्थिति

आरिफ मोहम्मद खां

राज्यपाल, बिहार

नीतीश कुमार

मुख्यमंत्री, बिहार

अश्विनी वैष्णवकेंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण,
इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री**अर्जुन राम मेघवाल**केंद्रीय विधि एवं न्याय (स्वतंत्र प्रभार)
तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री**नित्यानन्द राय**

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री

सतीश चंद्र दुबे

केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री

**भारतीय रेल**